



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

शासिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 6, 1993/अग्राहायना 15, 1915

No. 13] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 6, 1993/AGRAHAYANA 15, 1915

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1993

का.नि.आ. 17(अ):—केन्द्रीय सरकार सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 191 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेना नियम, 1954 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना (संशोधन) नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सेना नियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 14 के उपनियम (4) और उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जायेंगे, अर्थात् :—

(4) उपनियम (2) या उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार को कोई मामला भेजने समय तक सेनाध्यक्ष अपनी सिफारिश करेगा कि क्या आफिसर की सेवा पर्यवसित की जानी चाहिये

या नहीं की जानी चाहिये और यदि ऐसा है तो क्या आफिसर :

(क) को सेवा से पदच्युत किया जाना चाहिये, या
(ख) को सेवा से हटाया जाना चाहिये, या
(ग) को सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिये।

(5) केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, रिपोर्ट और आफिसर की प्रतिरक्षा पर, यदि कोई हो, और थल सेना अध्यक्ष की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात्,—

(क) आफिसर को पेंशन या उपदान सहित या उसके बिना पदच्युत कर सकेगी या हटा सकेगी, या

(ख) पेंशन या उपदान सहित उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर सकेगी।

3. उक्त नियमों के नियम 16क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

“16क अधिकारियों की सेवानिवृत्ति—(1) केन्द्रीय

सरकार के अथवा उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के आदेशों के अधीन अधिकारी उस मास की अंतिम तारीख के अपराह्न से सेवानिवृत्त होने के लिये दायी होंगे जिस मास के वे—

(क) उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट आयु सीमा प्राप्त करते हैं, या

(ख) उपनियम 5(च) (2) और (छ) (2) में विनिर्दिष्ट नियुक्ति की पदावधि इन दोनों में से जो पहले हो, पूरा करते हैं।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित होंगे :

(क) सेना चिकित्सा को, सेना दंतचिकित्सा को और सेना नर्सिंग सेवा के मामले में महानिदेशक सशस्त्र बल, चिकित्सा सेवा ;

(ख) कर्नल की पंक्ति से नीचे के उस कोर के अधिकारियों के मामले के अपर महानिदेशक, अश्व और पशु चिकित्सा को ;

(ग) सैनिक फार्म के कर्नल की पंक्ति से नीचे के अधिकारियों के मामले में उप महानिदेशक सैनिक फार्म ;

(घ) अन्य सभी अधिकारियों के मामले में सैनिक सचिव, सेना मुख्यालय।

(3) सेवानिवृत्ति आदेश में, सेवानिवृत्त जिस तारीख से लागू होगी वह विनिर्दिष्ट होगी और उपनियम (4) के उपबंधों के अधीन रहने हुए अधिकारी को उस तारीख से कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।

(4) ऐसा अधिकारी जिसने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है अथवा जो अपनी पदावधि पूर्ण हो जाने पर सेवानिवृत्त होने वाला है, केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवा की आवश्यकताओं के अनुसार और अवधि के लिये सेवा में रखा जा सकेगा।

(5) सेवानिवृत्ति की आयु निम्नलिखित होगी :

(क) कबचित कोर, पैदल, तोप इंजीनियर और सिगनल कोर के अधिकारियों के लिये :—

मेजर की पंक्ति तक जिसमें यह पंक्ति भी सम्मिलित है	50 वर्ष
लैफ्टिनेंट कर्नल (काल वेतनमान)	51 वर्ष
लैफ्टिनेंट कर्नल (चयन)	52 वर्ष
कर्नल	52 वर्ष
ब्रिगेडियर	54 वर्ष
मेजर जनरल	56 वर्ष
लैफ्टिनेंट जनरल	58 वर्ष
जनरल	60 वर्ष

(ख) सेना सेवा कोर (जिसके अन्तर्गत खाद्य निरीक्षण संगठन नहीं है (सेना आईनस कोर, विद्युत् और यांत्रिक इंजीनियर, पायनियर कोर और आसूचना कोर के अधिकारियों के लिये—

कर्नल की पंक्ति तक जिसमें यह पंक्ति भी सम्मिलित है	52 वर्ष
ब्रिगेडियर	54 वर्ष
मेजर जनरल	56 वर्ष
लैफ्टिनेंट जनरल	58 वर्ष

(ग) खाद्य निरीक्षण संगठन के अधिकारियों के लिये, लैफ्टिनेंट कर्नल (काल वेतनमान) की पंक्ति तक जिसमें यह पंक्ति भी सम्मिलित है

लैफ्टिनेंट कर्नल (चयन) 55 वर्ष

(घ) न्याय-महाधिवक्ता के विभाग, सेना शिक्षा कोर, सैनिक फार्म, विशेष सूची अधिकारियों (क्वार्टर मास्टर, तकनीकी अभिलेख अधिकारी और सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर (मास्टर एट आर्मस) तथा अश्व और पशु चिकित्सा कोर) के अधिकारियों के लिये —

कर्नल की पंक्ति तक जिसमें यह पंक्ति भी सम्मिलित है	55 वर्ष
ब्रिगेडियर	56 वर्ष
मेजर जनरल	57 वर्ष
लैफ्टिनेंट जनरल	58 वर्ष

(ङ) सेना चिकित्सा कोर, सेना दंत चिकित्सा कोर और सैनिक परिचर्या सेवा के अधिकारियों के लिये,

लैफ्टिनेंट कर्नल की पंक्ति तक जिसमें यह पंक्ति भी सम्मिलित है	55 वर्ष
कर्नल	57 वर्ष
ब्रिगेडियर	58 वर्ष
मेजर जनरल	59 वर्ष
लैफ्टिनेंट जनरल	60 वर्ष
सेना चिकित्सा कोर के सभी अधिकारी (अतकनीकी)	55 वर्ष

(च) (1) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में स्थायी रूप से उपनियुक्त अधिकारियों के लिये मेजर जनरल या समतुल्य पंक्ति तक जिसमें मेजर जनरल या समतुल्य पंक्ति भी सम्मिलित है 57 वर्ष

लेफ्टिनेंट जनरल

58 वर्ष

परन्तु मेजर जनरल या समतुल्य पंक्ति तक के अधिकारियों का दो बार पुनर्विलोकन किया जायेगा, एक 52 वर्ष की आयु पर और दूसरा 55 वर्ष की आयु पर जो उस आयु से परे सेवा में बने रहने के लिये उपयुक्तता अवधारित करने के लिये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन चयन बोर्ड द्वारा अपने अधिकथित मानदंड के अनुसार पर्याप्त समय पहले किया जायेगा जब तक कि अधिकारी स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति नहीं ले लेता है। वे अधिकारी जो इन दोनों में से किसी पुनर्विलोकन में सेवा में बने रहने के लिये अनुपयुक्त पाये जाते हैं, यथास्थिति, 52 वर्ष या 55 वर्ष सेवानिवृत्ति हो जायेंगे।

(2) लेफ्टिनेंट जनरल की अधिष्ठायी पंक्ति में कार्यकाल चार वर्ष होगा।

(छ) (1) क्वालिटी आण्डासत 'महानिदेशालय' में स्थायी रूप से उपनियुक्त अधिकारियों के लिये, मेजर जनरल या समतुल्य की पंक्ति तक जिसमें मेजर जनरल या समतुल्य की पंक्ति भी सम्मिलित है

57 वर्ष

लेफ्टिनेंट जनरल

58 वर्ष

परन्तु मेजर जनरल या समतुल्य पंक्ति तक के अधिकारियों का दो बार पुनर्विलोकन किया जायेगा, एक 52 वर्ष की आयु पर और दूसरा 55 वर्ष की आयु पर जो उस आयु से परे सेवा में बने रहने के लिये उपयुक्तता अवधारित करने के लिये निरीक्षण चयन बोर्ड द्वारा अपने अधिकथित मानदंड के अनुसार पर्याप्त समय पहले किया जायेगा। वे अधिकारी जो इन दोनों में से किसी पुनर्विलोकन में सेवा में बने रहने के लिये अनुपयुक्त पाये जाते हैं, यथास्थिति 52 वर्ष या 55 वर्ष की आयु होने पर सेवा निवृत्त हो जायेंगे।

(2) लेफ्टिनेंट जनरल की अधिष्ठायी पंक्ति में पदावधि चार वर्ष होगी।

(ज) भारतीय सर्वेक्षण में स्थायी रूप से उपनियुक्त इंजीनियरों के लिये समय-समय पर उन्हें लागू सिविल नियमों के अधीन।

(6) सेवा निवृत्ति के प्रयोजन के लिये नियुक्ति की पदावधि निम्नलिखित होगी—

(क) जनरल की पंक्ति में पदावधि अधिकतम तीन वर्ष होगी ;

(ख) ऐसे सेना चिकित्सा कोर अधिकारी जो लेफ्टिनेंट जनरल की पंक्ति धारण किये

हुए हैं उस पंक्ति में 4 वर्ष की एक पदावधि के लिये सेवा करेंगे :

परन्तु ऐसा अधिकारी, जो चिकित्सा सेवा महानिदेशक (सेना) या चिकित्सा सेवा महानिदेशक (नौसेना) या चिकित्सा सेवा महानिदेशक (वायुसेना) या समानिदेशक सशस्त्र बल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय या समादेशक सेना चिकित्सा कोर विद्यालय और केन्द्र लखनऊ या लेफ्टिनेंट जनरल की पंक्ति में अपर महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की नियुक्ति धारण किये हुए हैं, महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा रूप में अपनी नियुक्ति की दशा में, पांच वर्ष की सम्मिलित पदावधि के लिये सेवा करेगा।

(ग) मेजर जनरल की पंक्ति के सेना दंत चिकित्सा कोर के अधिकारियों की पदावधि अधिकतम 4 वर्ष होगी।

स्पष्टीकरण 1—इस नियम के प्रयोजन के लिये—

(क) "लेफ्टिनेंट कर्नल" से चयन द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सेना चिकित्सा कोर, सेना दंत चिकित्सा कोर और अश्व और पशु चिकित्सा कोर के पशु चिकित्सा काडर में के काल बेतनमान में का लेफ्टिनेंट कर्नल भी आता है :

(ख) "रैंक" से अधिष्ठायी रैंक अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2—इस नियम के प्रयोजन के लिये—

(क) उपनियम (5) में यथाविनिर्दिष्ट सेवानिवृत्ति की आयु उनके अपने अधिष्ठायी रैंकों में स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को लागू होगी।

(ख) सेना शिक्षा कोर, आसूचना कोर, अश्व और पशु चिकित्सा कोर, न्याय महाधिवक्ता का विभाग, पायोनियर कोर, सैनिक फार्म और विशेष सूची अधिकारी काडर में लेफ्टिनेंट जनरल/मेजर जनरल के रैंक में सेवानिवृत्ति की अनुबंधित आयु केवल तब लागू होगी जब ये रैंक यथास्थिति, कोर, विभाग या काडर में मजूर किये गये हैं।

(ग) आसूचना कोर, न्याय महाधिवक्ता के विभाग, सेना शिक्षा कोर, अश्व और पशु चिकित्सा कोर और सैनिक फार्म के ऐसे अधिकारी जिन्होंने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. ए 49453/एजी/पी एस/2(ए)/3770-एस डी (ए जी), तारीख 26 जुलाई, 1984 और ए 49453/एजी/पी एस 2(ए) लघु कोर-एस/डी (ए जी) तारीख 26 जुलाई, 1985 जिसे वे लागू थे के जारी किये जाने के पूर्व

विद्यमान भेदानिबृति की प्राप्ति से शामिल होने का विकल्प दिया था इस प्रकार शामिल होने रहेंगे” ।

4. उक्त नियमों के नियम 16 ख के उपनियम (1) में, “अनिवार्य” शब्द का लोप किया जायेगा।

5. उक्त नियमों के नियम 22 के स्थान पर, निम्न-लिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात्—

“22. आरोप की सुनवाई—

- (1) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध, जो अधिनियम के अधीन है, प्रत्येक आरोप की सुनवाई अभियुक्त की उपस्थिति में कमान आफिसर द्वारा की जायेगी। अभियुक्त अपने विरुद्ध किसी भी साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने और ऐसे किसी साक्षी को आहूत करने और अपनी उसकी प्रतिपरीक्षा लिये के ऐसा कोई कथन करने के लिये जो आवश्यक हो, पूर्ण स्वतंत्र होगा :

परन्तु जहां किसी अभियुक्त के विरुद्ध कोई आरोप किसी जांच न्यायालय द्वारा ऐसे अन्वेषण के परिणामस्वरूप उद्भूत होता है जिसमें नियम 180 के उपबंधों का उस अभियुक्त की बाबत अनुपालन किया गया, वहां कमान आफिसर उप-नियम (1) में दी गई प्रक्रिया को अभियुक्ति दे सकेगा।

- (2) कमान आफिसर उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए किसी आरोप को खारिज कर देगा यदि उसकी राय में साक्ष्य से यह दृष्टि नहीं होता कि अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है और वह ऐसा तब कर सकेगा जब उसका समाधान हो जाता है कि आरोप के संबंध में आगे कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए :

परन्तु कमान आफिसर ऐसे किसी आरोप को खारिज नहीं करेगा जिसका वह धारा 120 की उपधारा (2) के अधीन उममें यथा-यदि विनिर्दिष्ट वरिष्ठ प्राधिकारी को निर्देश किए बिना विचारण करने से विवर्जित है।

- (3) उपनियम (1) के अनुपालन के पश्चात् यदि कमान आफिसर की यह राय है कि आरोप के संबंध में आगे कार्यवाही की जानी चाहिए तो वह युक्ति-युक्त समय के भीतर

(क) मामले की परिशिष्ट 3 में की रीति और प्ररूप के अनुसार, धारा 80 के अधीन निपटा देगा, या

(ख) मामला उचित वरिष्ठ सेना प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर देगा; या

(ग) साक्ष्य को लेखबद्ध करने के प्रयोजन के लिए मामले को स्थगित कर देगा; या

(घ) यदि अभियुक्त वरिष्ठ आफिसर से नीचे के रैंक का है तो उसका विचारण संक्षिप्त सेना न्यायालय द्वारा करने के लिए आदेश देगा :

परन्तु कमान आफिसर अभिकथित अपराधी का संक्षिप्त सेना न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने के आदेश के मामले को उस आफिसर को निर्दिष्ट किए बिना नहीं देगा जो डिस्ट्रिक्ट सेना न्यायालय या सक्रिय सेवा की दशा में, समरी जनरल सेना न्यायालय संयोजित करने के लिए सशक्त है, किन्तु ऐसा आदेश दिया जा सकता है यदि—

(क) अपराध वह है जिसका विचारण, मामले को उक्त आफिसर को निर्दिष्ट किए बिना, समरी सेना न्यायालय द्वारा किया जा सकता है; या

(ख) वह यह समझता है कि तुरन्त कार्यवाही करने का कोई गम्भीर कारण है और ऐसा निर्देश अनुशासन में बाधा डाले बिना नहीं किया जा सकता है।

(4) जहां इस नियम के उपनियम (3) के अनुसार लिए गए साक्ष्य से ऐसे अपराध से बिना कोई अपराध प्रकट होता है जो अन्वेषण का विषय था वहां कमान आफिसर इस प्रकार लिए गए साक्ष्य तथा मूल आरोप के अन्वेषण के आधार पर समुचित आरोप विरचित कर सकेगा।

6. उक्त नियमों के नियम 25 का लोप किया जाएगा।

7. उक्त नियमों के नियम 26 में,

(1) उपनियम (1) में, या (उस आफिसर की दशा में जहां साक्ष्य की कोई संक्षिप्ति नहीं है पेश किए जाने वाले साक्ष्य की संक्षिप्ति शब्दों का लोप किया जाएगा।

(2) उपनियम (3) में, “या सार” शब्दों का लोप किया जाएगा।

8. उक्त नियमों के नियम 33 के उपनियम (7) में निम्नलिखित शब्दों का लोप किया जाएगा, अर्थात्—

“या उस आफिसर की दशा में जहां, साक्ष्य का संक्षेप नहीं है, साक्ष्य की संक्षिप्ति देगी”।

9. उक्त नियमों के नियम 36 में “25” श्रंको का लोप किया जाएगा।

10. उक्त नियमों के नियम 37 के उपनियम (4) में, दोनों स्थानों पर आने वाले “या संक्षिप्ति” शब्दों का लोप किया जाएगा।

11. उक्त नियमों के नियम 52 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम 2क अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2क, जहां कोई अभियुक्त दोषी होने का अभिवाक करता है वहां ऐसे अभिवाक और इस नियम के उपनियम (2) के अनुपालन का तथ्य न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रीति में अभिलिखित किया जाएगा।

अभियुक्त के दोषी होने का अभिवाक अभिलिखित करने के पूर्व न्यायालय ने अभियुक्त को ऐसे आरोप (आरोपों) के अर्थ स्पष्ट कर दिए थे जिनके/जिनके लिए उसने दोषी होने का अभिवाक किया था और यह अभिलिखित किया था कि अभियुक्त ने ऐसे आरोप (आरोपों) की प्रकृति को समझ लिया था जिसके/जिनके लिए उसने दोषी होने का अभिवाक किया था। न्यायालय ने अभियुक्त को अभिवाक के साधारण प्रभाव और प्रक्रिया में उस अंतर की भी जानकारी दे दी थी जिसका उक्त अभिवाक के परिणामस्वरूप अनुसरण किया जाएगा। न्यायालय ने अपना यह समाधान करने पर कि अभियुक्त आरोप (आरोपों) और दोषी होने के अपने अभिवाक के प्रभाव को समझता है, उसे स्वीकार और अभिलिखित करता है। नियम 52 (2) के उपबंधों का इस प्रकार अनुपालन हो जाता है।

12. उक्त नियमों के नियम 53 के उपनियम (1) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) धारा 122 में यथाअधिकथित विचारन की परिसीमा की कालावधि समाप्त हो गई है”।

13. उक्त नियमों के नियम 54 में “या सार” शब्दों का जहां-जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा।

14. उक्त नियमों के नियम 57 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“57. कोई मामला न चलने का अभिवाक—

- (1) अभियोजन की ओर से मामले की समाप्ति पर अभियुक्त यह अभिवाक प्रस्थापित कर सकेगा कि किसी एक या अधिक आरोपों की बाबत अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला स्थापित नहीं हुआ है, अतः उसे उस आरोप या उन आरोपों के लिए अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।
- (2) जहां अभियुक्त ऐसा अभिवाक लाता है वहां अभियोजक उसके प्रत्युत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त उत्तर दे सकेगा।
- (3) न्यायालय अभिवाक पर बंद न्यायालय में विचार करेगा और अभिवाक को तब तक अनुज्ञात नहीं

करेगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि—

- (क) अभियोजन ने यथाअधिकथित आरोप या आरोपों पर प्रथम दृष्टया कोई मामला स्थापित नहीं किया है, और
- (ख) दिए गए साक्ष्य पर धारा 139 या नियम 62 के उपनियम (4) के अधीन विशेष निष्कर्ष निकालने की उसे छूट नहीं होगी।
- (4) यदि न्यायालय अभिवाक को अनुज्ञात करता है तो वह ऐसे आरोप या आरोपों पर जिसमें अभिवाक संबंधित है, “दोषी न होने” का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और पुष्टीकरण के अधीन रहने हुए खुले न्यायालय में तुरंत निष्कर्ष की घोषणा करेगा।
- (5) यदि न्यायालय अभिवाक को उलट देता है तो वह विचारण में आगे कार्यवाही करेगा।

(6) यदि न्यायालय को अभिवाक की विधि मान्यता के बारे में कोई संदेह है तो वह मामले को संयोजक प्राधिकारी को निर्देशित कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए भी स्थगित कर सकेगा।

(7) न्यायालय, स्वप्रेरण से अभियोजन के लिए मामला बंद हो जाने के पश्चात और अभियोजक की सुनवाई करने के पश्चात अभियुक्त को आरोप के लिए “दोषी नहीं” पा सकता है और पुष्टीकरण के अधीन रहते हुए खुले न्यायालय में तुरंत निष्कर्ष की घोषणा कर सकता है।

(8) न्यायालय नियम 62 के उपनियम (1) के अनुसार अभिवाक पर निष्कर्ष निकालने समय संश्लिप्त कारणों को अभिलिखित करेगा।”

15. उक्त नियमों के नियम 58 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“58. अभियुक्त और प्रतिरक्षा साक्षियों की परीक्षा

(1) (क) प्रत्येक विचारण में, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में आने वाली किसी परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अभियुक्त को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए न्यायालय का न्याय-अधिवक्ता।

- (1) किसी भी प्रक्रम पर अभियुक्त को पूर्व चेतावनी दिए बिना उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो वह आवश्यक समझे,
- (2) अभियोजन की ओर से मामले की समाप्ति के पश्चात और अपनी प्रतिरक्षा के लिए उसकी ग्राह्य किए जाने के पूर्व उससे मामले के बारे में साधारणतः प्रश्न पूछ सकेगा।

(ख) अभियुक्त को उस समय कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी जब खंड (क) के अधीन उसकी परीक्षा की जाती है।

(ग) अभियुक्त उपरोक्त खंड(क) में निर्दिष्ट प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार करने के कारण या उनको ऐसे उत्तर देने के कारण, जिसके सही न होने की उसे जानकारी है, दंड का भागी नहीं होगा।

(2) अभियोजन की ओर से मामले की समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारी या न्याय अधिवक्ता, यदि कोई हो, अभियुक्त को यह स्पष्ट करेगा कि वह अपने विरुद्ध आरोप (ों) के विषय के बारे में अपना विवरण देने हुए मौखिक या लिखित रूप में अशपथित कथन कर सकेगा या यदि वह ऐसा चाहता है तो वह अपने विरुद्ध या उसी विचारन में उसके साथ आरोपित किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आरोप (आरोपों) के नासाबित होने के संबंध में सबूत में शपथ या प्रतिज्ञान पर साक्षी के रूप में साक्ष्य दे सकेगा,

परन्तु—

(क) उसे लिखित रूप में अपने स्वयं के अनुरोध के सिवाय साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जाएगा,

(ख) साक्ष्य देने में उसकी असफलता किसी पक्षकार या न्यायालय द्वारा किसी टिप्पण का विषय नहीं बनाई जाएगी या उसके विरुद्ध या उसी विचारन में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई उपधारणा उत्पन्न नहीं करेगा,

(ग) यदि वह शपथ या प्रतिज्ञान पर साक्ष्य देता है तो प्रतिरक्षा की ओर से प्रथम साक्षी के रूप में उसकी परीक्षा की जाएगी और वह अभियोजक द्वारा प्रति परीक्षा किए जाने के लिए और न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने के लिए दायी होगा।

(3) तब अभियुक्त अपने साक्षी आहूत कर सकेगा, जिसके अन्तर्गत यदि वह ऐसी वांछा करता है तो चरित्र के बारे में साक्षी भी होगा। यदि अभियुक्त मामले के तथ्यों के बारे में अपने से भिन्न साक्षियों को आहूत करना चाहता है तो वह प्रतिरक्षा की ओर से साक्ष्य दिए जाने से पूर्व प्रारंभिक संबोधन कर सकेगा।”

16. उक्त नियमों के नियम 59 के स्थान पर निम्न-लिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“59. अंतिम संबोधन—साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात् अभियोजक अंतिम संबोधन कर सकेगा और यथास्थिति, अभियुक्त या उसका काउंसेल या प्रतिरक्षा अधिकारी उत्तर देने के लिए हकदार होगा :

परन्तु जहां अभियुक्त द्वारा कोई विधि का प्रश्न उठाया जाता है वहां अभियोजक न्यायालय की अनुज्ञा से, उस प्रश्न के बारे में अपना निवेदन कर सकेगा।”

17. उक्त नियमों के नियम 59-क का लोप किया जाएगा।

18. उक्त नियमों के नियम 62 के उपनियम(1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) ऐसे प्रत्येक आरोप पर जिम का अभियुक्त पर दोषारोपण किया गया है निष्कर्ष अभिलिखित किया जाएगा और इन नियमों में जैसा उल्लिखित है उसके सिवाय “दोषी होने” या “दोषी न होने” मात्र के निष्कर्ष के रूप में अभिलिखित किया जायेगा। प्रत्येक आरोप के निष्कर्ष अभिलिखित करने के पश्चात् न्यायालय उसके समर्थन में संक्षिप्त कारण देगा, न्याय अधिवक्ता या ऐसा कोई नहीं है द्वारा पीठासीन अधिकारी ऐसे संक्षिप्त कारणों को कार्यवाहियों में अभिलिखित करेगा या कराएगा। उपर्युक्त अभिलेख पीठासीन अधिकारी या न्याय अधिवक्ता यदि कोई हो द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जायेगा।”

19. उक्त नियमों के नियम 68 के स्थान पर निम्न-लिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“68. पुनरीक्षण—(1) यदि निष्कर्ष धारा 160 के अधीन पुनरीक्षण के लिए वापिस भेजा जाता है तो न्यायालय खुले न्यायालय में पुनः समवेत होगा, पुनरीक्षण आदेश पढ़ा जाएगा और यदि न्यायालय को नए सिरे से साक्ष्य लेने के लिए निदेश है तो ऐसा साक्ष्य भी खुले न्यायालय में लिया जायेगा।

(2) वहां के सिवाय जहां न्यायालय को नए सिरे से साक्ष्य लेने के लिए निदेश है कोई नया साक्ष्य नहीं दिया जायेगा।

(2) न्यायालय, अभियोजक से अनुरोध किए जाने पर न्यायालय के हित में पुनरीक्षण के दौरान प्रतिरक्षा की ओर से किसी साक्षी द्वारा किए गए तात्त्विक कथन का खंडन करने के प्रयोजन के लिए हिसी भागी को बुलाए जाने या पुनः बुलाए जाने के लिए अनुज्ञा कर सकेगा।

(4) खुले न्यायालय में पुनरीक्षण आदेश पढ़े जाने के पश्चात्, चाहे पुनरीक्षण निष्कर्ष या दंडादेश का हो और उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) के अनुसार या साक्ष्य, यदि कोई है, लेने के पश्चात् अभियोजक और अभियुक्त को नियम 59 में यथा-अधिकथित क्रमानुसार न्यायालय को संबोधित करने का और अवसर दिया जायेगा। यदि आवश्यक हो तो न्याय अधिवक्ता यदि कोई हो, (अतिरिक्त) साक्ष्य का सारांश तैयार कर सकेगा और मामले से संबंधित विधि पर न्यायालय को सलाह दे सकेगा। इसके पश्चात् न्यायालय बंद न्यायालय में यथास्थिति अपने निष्कर्ष या दंडादेश पर विचार विमर्श करेगा।

(5) जहां निष्कर्ष पुनरीक्षण के लिए वापस लिया जाता है और न्यायालय अपने पुराने निष्कर्ष से सहमत नहीं है वहां वे निष्कर्ष और दंडादेश को प्रतिरोधित करेगा और नियम 62 में अधिकथित रीति में

नया निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और यदि ऐसे नए निष्कर्ष में कोई संज्ञादेश अंतर्भूत है तो नियम 64 का अनुपालन करने के पश्चात् न्यायालय संज्ञादेश पारित कर सकेगा।

(6) जहां केवल संज्ञादेश ही पुनरीक्षण के लिए वापस भेजा जाता है वहां न्यायालय निष्कर्ष का पुनरीक्षण नहीं करेगा।

(7) पुनरीक्षण के पश्चात् पीठासीन अधिकारी न्यायालय के विनिश्चय पर तारीख डालेगा और हस्ताक्षर करेगा और न्याय अधिवक्ता, यदि कोई हो, द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने पर कार्यवाहियां पृष्ठ करने के लिए तुरन्त पारेषित कर दिया जायगा।”

20. उक्त नियमों के नियम 92 के उपनियम (1) में, “अंग्रेजी भाषा में” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में”।

21. उक्त नियमों के नियम 96 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“96. जनरल और डिस्ट्रिक्ट सेना न्यायालय में काउंसिल अनुज्ञात :— प्रत्येक जनरल और डिस्ट्रिक्ट सेना न्यायालय में काउंसिल अभियोजक और अभियुक्त की ओर से उपसंज्ञात होने के लिए अनुज्ञात होगा : परन्तु संयोजक अधिकारी यह घोषित कर सकेगा कि उसमें काउंसिल की उपसंज्ञाती की अनुज्ञा देना समीचीन नहीं है और ऐसी घोषणा किसी विशिष्ट स्थान में अधिघोषित सब जनरल और डिस्ट्रिक्ट सेना न्यायालयों को बाबत या किसी विशिष्ट जनरल या डिस्ट्रिक्ट सेना न्यायालय की बाबत की जा सकेगी और कार्यकारी सेवा के बारे में ऐसे आरक्षण के अधीन या अन्यथा जैसा समीचीन समझा जाए, की जा सकेगी।

22. उक्त नियमों के नियम 106 के उपनियम (i) में, “अंग्रेजी भाषा में” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“हिन्दी या अंग्रेजी में”।

23. उक्त नियमों के नियम 115 के उप नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम (2क) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(2क) जहां कोई अभियुक्त दोषी होने का अभिवाक करता है वहां ऐसा अभिवाक और इस नियम के उपनियम (2) के अनुपालन का तथ्य न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रीति में अभिलिखित किया जाएगा, अभियुक्त के दोषी होने का अभिवाक अभिलिखित करने के पूर्व न्यायालय ने अभियुक्त को ऐसे आरोप (अरोपों) के अर्थ स्पष्ट कर दिए थे जिसके/जिनके लिए उसने दोषी होने का अभिवाक किया था और यह अभिलिखित

किया था कि अभियुक्त ने ऐसे आरोप (आरोपों) की प्रकृति को समझ लिया था जिसके/जिनके लिए उसने दोषी होने का अभिवाक किया था। न्यायालय ने अभियुक्त को अभिवाक के साधारण प्रभाव और प्रक्रिया में उस अंतर की भी जानकारी दे दी थी जिसका उक्त अभिवाक के परिणामस्वरूप अनुसरण किया जायगा। न्यायालय ने अपना यह समाधान कर लेने पर कि अभियुक्त आरोप (आरोपों) और दोषी होने के अपने अभिवाक के प्रभाव को समझता है, उसे स्वीकार और अभिलिखित करता है। नियम 115(2) के उपबंधों का इस प्रकार अनुपालन हो जाता है।”

24. उक्त नियमों के नियम 118 में निम्नलिखित शब्दों का लोप किया जाएगा, अर्थात् :—

“किन्तु न्यायालय ऐसे इन्कार या उत्तरों से ऐसे अनुमान लगा सकेगा जैसे वह न्यायसंगत समझता है”।

25. उक्त नियमों के नियम 134, 135 और 136 में “या संक्षिप्ती” शब्दों का लोप किया जायगा।

26. उक्त नियमों के नियम 145 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“145 उन्मत्तता का निष्कर्ष—

(क) जहां न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त चित्तविकृति के कारण अपनी प्रतिक्रिया करने के अयोग्य है अथवा उससे अक्षय्य कार्य किया गया है। किन्तु चित्तविकृति के कारण वह कार्य की प्रकृति समझने के योग्य नहीं था या कि वह कार्य गलत था या विधि विरुद्ध था तो न्यायालय उसके समर्थन में संक्षिप्त कारण देगा। न्याय अधिवक्ता यदि कोई हो, या पीठासीन अधिकारी या समरी सेना न्यायालय, की दशा में विचारण करने वाले अधिकारी ऐसे संक्षिप्त कारणों को कार्यवाहियों में अभिलिखित करेगा या करवाएगा।

(2) पीठासीन अधिकारी या समरी सेना न्यायालय की दशा में विचारण करने वाले अधिकारी उपयुक्त अभिलेख पर तारीख डालेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और कार्यवाहियां न्याय अधिवक्ता यदि कोई हो, द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के पश्चात् तुरन्त यथास्थिति पृष्ठ करने वाले आकिसर को या न्यायालय के निष्कर्ष के संबंध में कार्यवाही करने के लिए धारा 162 के अधीन सशक्त प्राधिकारी को पारेषित कर दी जाएगी।”

27. उक्त नियमों के नियम 150 के उपनियम (3) में “सार दंडप्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का अधिनियम 5) की धारा 476” शब्दों और अंकों के स्थान पर “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा 340” शब्द और अंक रखा जाएगा।

28. उक्त नियमों के नियम 159 में,

(क) उपनियम (1) में निम्नलिखित शब्दों का लोप किया जाएगा, अर्थात् :—

“चाहे विधि परामर्शी या कोई अन्य कोई व्यक्ति”

(ख) उपनियम (2) में निम्नलिखित शब्दों का लोप किया जाएगा, अर्थात् :—

“किन्तु न्यायालय ऐसे इन्कार या उत्तरों से ऐसे अनुमान लगा सकेगा जैसे वह उचित समझता है।”

29. उक्त नियमों के नियम 160 के उपनियम (3) में “या संक्षिप्ती” शब्दों का लोप किया जाएगा।

30. उक्त नियमों के नियम 164 में :—

(i) “नियम 25 (आफिसर के विरुद्ध आरोप पर प्रश्रिया)” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा।

(ii) “नियम 95 (प्रतिरक्षा आफिसर और अभियुक्त का मित)” शब्दों, अंकों और कोष्ठक के पश्चात् निम्नलिखित शब्द, अंक और कोष्ठक अंतस्थापित किए जाएंगे अर्थात् (नियम 96 कतिपय जनरल और डिस्ट्रिक्ट सेना न्यायालयों में अनुज्ञात काउंसल) (नियम 97 काउंसल की उपसंज्ञा के लिए अपेक्षा), नियम 98 (अभियोजक की ओर से काउंसल) नियम 99 (अभियुक्त की ओर से काउंसल), नियम 100 (काउंसल के बारे में साधारण नियम), नियम 101 (काउंसल की अर्हताएं)।”

31. उक्त नियमों के नियम 168 के उपनियम (2) में, “या फील्ड दंड भी है, ‘और’ या जब तक कि फील्ड दंड पूरा नहीं हो जाता है, जब तक कि ऐसा फील्ड दंड का मक्षम प्राधिकारी द्वारा परिहार्य नहीं कर दिया जाए” शब्दों का लोप किया जायगा।

32. उक्त नियमों के नियम 170 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“170. मृत्यु दंडादेश के विरुद्ध याचिका के लिए अवसर :

(1) मृत्यु दंडादेश की पुष्टि करते समय पुष्टि करने वाले प्राधिकारी वह कालावधि विनिर्दिष्ट करेगा जिसके भीतर दंडादिष्ट व्यक्ति, उसे दंडादेश प्रख्यापित किए जाने के पश्चात्, अपने विरुद्ध सेना न्यायालय के निष्कर्ष या दंडादेश के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध मृत्यु दंडादेश की पुष्टि की गई है प्रख्यासन के समय धारा 164 की उपधारा (2) के अधीन अपने अधिकारों के बारे में और पुष्टि करने वाले प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट उस कालावधि के बारे में सूचित किया जाएगा

जिसके भीतर यदि वह ऐसी वांछा करता है तो सेना न्यायालय के निष्कर्ष या दंडादेश के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध मृत्यु दंडादेश की पुष्टि कर दी गई है निष्कर्ष या दंडादेश के विरुद्ध की गई प्रत्येक याचिका और ऐसी याचिका के संबंध में प्रत्येक आदेश जहाँ पुष्टि करने वाले प्राधिकारी थल सेना अध्यक्ष या केन्द्रीय सरकार है वहाँ सेना मुख्यालय में एडजुटेंट जनरल की मार्फत और किसी अन्य दशा में पुष्टि करने वाले आफिसर की मार्फत पारित किया जायगा।

(4) मृत्यु दंडादेश उपनियम (1) के अधीन पुष्टि करने वाले प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति तक यह कार्यान्वित नहीं किया जाएगा या यदि इस प्रकार विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर दंडादेश के अधीन व्यक्ति सेना न्यायालय के निष्कर्ष या दंडादेश के विरुद्ध कोई याचिका प्रस्तुत कर देता तो जब तक ऐसी याचिका को अंतिम रूप में निपटान के लिए विधिक रूप से मजबूत प्राधिकारी याचिका पर विचार करने के पश्चात् यह आदेश नहीं दे देता है कि मृत्यु दंडादेश कार्यान्वित किया जाए।”

33. उक्त नियमों के नियम 170 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“170-क. मृत्यु वारंट—(1) सेना, सेना कोर या डिवाइजन का समादेश करने वाले आफिसर या फील्ड में बलों का समादेश करने वाले आफिसर प्रोवोस्ट मार्शल या लेफ्टिनेंट कर्नल से अनिवार्य पंक्ति के किसी अन्य अधिकारी को जो अधिनियम के अधीन प्राप्त मृत्यु दंडादेश को सम्बन्ध निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा, नाम निर्दिष्ट करेगा और ऐसे आफिसर को परिशिष्ट-5 में सुसंगत प्ररूप में मृत्यु वारंट जारी करेगा।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी मृत्यु वारंट तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि नियम 170 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए मृत्यु दंडादेश कार्यान्वित किया जाएगा।

(3) अधिनियम के अधीन पारित कोई मृत्यु दंडादेश तब तक कार्यान्वित नहीं किया जाएगा जब तक कि मृत्यु वारंट उपनियम (1) के अधीन प्रोवोस्ट मार्शल या अन्य आफिसर द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है।

(4) यदि उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की यह राय है कि मृत्यु दंडादेश सिविल कारागार में कार्यान्वित किया जाए तो वह दंडादेश के पुष्टिकरण को प्रमाणित करते हुए पुष्टि करने वाले प्राधिकारी के आदेश सहित उस वारंट को परिशिष्ट-5 में दिए गए प्ररूप में से एफ में दंडादेश के निष्पादन के लिए सिविल कारागार को अप्रेषित करेगा।

170. ख. मृत्यु दंडादेश का निष्पादन :—(1) मृत्यु वारंट की प्राप्ति पर नियम 170 (क) के उपनियम (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्रोवोस्ट मार्शल या अन्य अधिकारी :—

(क) दंडादिष्ट व्यक्ति को यथासंभव शीघ्र कोई तारीख की सूचना देगा जिसको दंडादेश कार्यान्वित किया जाएगा,

(ख) यदि दंडादिष्ट व्यक्ति को नियम 169 के अधीन किसी सिविल कारागार के मुपुर्दे किया गया है तो परिशिष्ट 5 में दिए गए प्ररूपों में से किसी एक में वारंट निकाल कर ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा प्राप्त करेगा, और

(ग) मृत्यु वारंट की अपेक्षानुसार और उन साधारण या विशेष अनुदेशों के अनुसार जो समय-समय पर थल सेना-ध्यक्ष द्वारा या उसके प्राधिकारी के अधीन दिए जाएं, दंडादेश को क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही ही करेगा।

(2) अधिनियम के अधीन पारित मृत्यु दंडादेश निष्पादन के दौरान नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के सिवाय कोई व्यक्ति ऐसे आफिसर के प्राधिकार के बिना उपस्थित नहीं होगा जिसने मृत्यु वारंट जारी किया था। निम्नलिखित व्यक्ति मृत्यु दंडादेश के निष्पादन में उपस्थित होंगे :—

(क) प्रोवोस्ट जनरल या ऐसा अन्य आफिसर जो इन नियमों के अनुसार दंडादेश के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी है।

(ख) संध के सशस्त्र बलों का आयुक्त चिकित्सा आफिसर।

(ग) ऐसे आफिसर द्वारा जिसने मृत्यु वारंट जारी किया था, नामनिर्दिष्ट कोई ऐसा आफिसर जो दंडादेश अधीन व्यक्ति की इस रूप में पहचान करने के योग्य है कि वह मृत्यु वारंट उल्लिखित में वर्णित व्यक्ति है और ऐसा व्यक्ति है जिसका वारंट सेना न्यायालय द्वारा विचार और दंडादिष्ट किया गया था।

(घ) ऐसे अनायुक्त आफिसर जो प्रोवोस्ट मार्शल या पूर्वोक्त आफिसर द्वारा रक्षार्थ और सुरक्षा प्रयोजनों के लिए या निष्पादन में सहायता करने के लिए रखा जाए।

(ङ) यदि निष्पादन किसी सेना यूनिट में कार्यान्वित किया जाता है तो ऐसे आफिसर जो ऐसी यूनिट के तत्समय का कमांड आफिसर समादेशक।

(3) मृत्यु दंडादेश कार्यान्वित किए जाने के पश्चात् यथास्थिति प्रोवोस्ट मार्शल या नियम 170 के उपनियम (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट अन्य आफिसर या सिविल कारागार का अधीक्षक मृत्यु वारंट के भाग-II और भाग-III को पूरा करेगा या करवाएगा और अनावश्यक बिलंब के बिना पूर्ण किया गया मृत्यु वारंट उस आफिसर को लौटा देगा जिसने उसे जारी किया था।

34. उक्त नियमों के नियम 172 और नियम 172 से 176 (जिसके अंतर्गत ये दोनों नियम सम्मिलित हैं) के पूर्व "धारा-7—गोल्ड डंड" शीर्षक का जोड़ दिया जाएगा।
2787 GI/93—2

35. उक्त नियमों के नियम 179 के उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5-क." किसी साक्षी को न्यायालय को समवेत करने वाले आफिसर के हस्ताक्षर से किए गए आदेश द्वारा हाजिर होने के लिए सम्मन किया जा सकेगा। सम्मन परिशिष्ट 3 में उपबंधित प्ररूप के होंगे।

36. उक्त नियमों के नियम 182 के स्थान पर निम्न लिखित नियम रखा जाएगा :—

"182. जांच न्यायालय की कार्यवाहियों का साक्ष्य से ग्राह्य न होना : जांच न्यायालय की कार्यवाहियां या जांच न्यायालय में की गई कोई संस्वीकृति, कथन या किसी प्रश्न का उत्तर अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा और न न्यायालय की कार्यवाहियों की बाबत कोई साक्ष्य किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध तब के सिवाय दिया जाएगा जब न्यायालय के सामने जानबूझ कर झूठा साक्ष्य देने के लिए ऐसे व्यक्ति का विचार न किया जाए।"

परन्तु इस नियम की कोई बात किसी साक्षी की प्रति-परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए कार्यवाहियों को अभि-योजन या प्रतिरक्षा की ओर से प्रयोग किए जाने निवारित नहीं करेगी।

37. उक्त नियमों के नियम 186 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) सेना, सेना को डिजीजन या स्वतंत्र ब्रिगेड को समादेश देने वाले आफिसर होने या चोगी की परिस्थितियों के बारे में अपनी राय अभिलिखित करेगा और खोए हुए या चोरी गए हथियार या शस्त्र के भाग के लिए ऐसे शस्त्र या शस्त्र के भाग के चालू सरकारी मूल्य की राशि तक श्वर आयुक्त आफिसरों, वारंट आफिसरों, अनायुक्त आफिसरों और ऐसी यूनिट के आदमियों पर या उनमें से उत्तमों पर जिनके बारे में वह समझता है कि वे घटना के लिए उत्तर-दायी होने चाहिए, सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।"

38. उक्त नियमों के नियम 193 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"193. धारा 90(1) और 91(1) के अधीन विहित आफिसर द्वारा 90 के खंड (1) और धारा 91 के खंड (1) के प्रयोजनों के लिए विहित आफिसर थल सेनाध्यक्ष या सेना समादेशक आफिसर होगा।"

39. उक्त नियमों के परिशिष्ट 3 में—

(क) भाग 1 में, आई ए एफ डी—905 (अभियुक्त के शील के बारे में विवरण और उसकी सेवा की विनिर्दिष्टियां (पैरा 9) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9. अभियुक्त उसी मामले के अन्वेषण, जांच या विश्लेषण के दौरान दिनों से सिविल

अभिरक्षा में और दिनों से सैनिक अभिरक्षा में, जिनका कुल योग दिन हुआ, गिरफ्तार/परिरुद्ध है”।

(ख) भाग-III में, “माक्षियों को समनों का प्ररूप” “(ख) सेना न्यायालय के मामले में प्रारूप और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

(ग) जांच न्यायालय के मामले में आई.ए.एफ.डी. 9199 सेवा में.....

जात हो कि का अन्वेषण करने के लिए तारीख को पर संयोजित होने के लिए जांच न्यायालय को आदेश दिया गया है। मैं, आपको (क) (ख) को तारीख (दिन) बजे (स्थान) पर उक्त न्यायालय की बैठक में साक्षी के रूप में हाजिर होने के लिए और इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित दस्तावेजों अर्थात् अपने साथ लाने के लिए और दिन प्रतिदिन इस प्रकार हाजिर होने के लिए समन करता हूँ और ऐसा करने की तब तक अपेक्षा करता हूँ जब तक आपको सम्यक रूप से उन्मोचित न कर दिया जाए। उपस्थित होने में चूक करने के परिणाम के भागी आप होंगे।

आज 19.....केमास केदिन मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

हस्ताक्षर

जांच न्यायालय का संयोजक आफिसर

40. उक्त नियमों के परिशिष्ट 4 में, भाग II “सेना अधिनियम की धारा 168, धारा 169 (2) और धारा 173 के अधीन वारंट” में,—

(क) प्ररूप ख में,—

(1) “आज 19.....केमास केदिन मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया” वाक्य में पूर्व, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“..... (नाम) द्वारा उसी मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान, सिविल अभिरक्षा/सैनिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि (च) है और उक्त अवधि (च) का कारावास के उपर्युक्त दंडादेश में से मुजरा किया जाएगा”।

(2) क्रम संख्यांक : (च) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(च) उसी मामले के अन्वेषण, जांच या विचार के दौरान सैनिक/सिविल अभिरक्षा में बिताई गई निश्चित अवधि (वर्ष, मास और दिन) भरें।”

(ख) प्रारूप ग में,—

(1) “आज 19.....केमासदिन मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया” वाक्य में पूर्व, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“..... (नाम) द्वारा उसी मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान, सिविल अभिरक्षा/सैनिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि (च) है और उक्त अवधि (च) का कारावास के उपर्युक्त दंडादेश में मुजरा किया जाएगा।”

(2) क्रम संख्यांक (घ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(घ) उसी मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान सैनिक/सिविल अभिरक्षा में बिताई गई निश्चित अवधि (वर्ष, मास और दिन) भरें।”

41. उक्त नियमों के परिशिष्ट 5 में—

(क) “सेना नियम 169, 170 और 171 के अधीन वारंट” शीर्षक में विद्यमान संख्या “170” के स्थान पर “170-क” संख्या रखी जाएगी।

(ख) “प्ररूप 1” में विद्यमान संख्या “170” के स्थान पर “170-क” संख्या रखी जाएगी।

निम्नलिखित नए प्ररूप जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

प्ररूप 1-क

सेना प्राधिकारियों द्वारा मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का वारंट

[सेना नियम 170-क और नियम 170 (ख)]

भाग—I

प्रेषिती

(क) (यूनिट) का (संख्यांक) रैंक, नाम को जिसे (ग) में हुए सेना न्यायालय (ख) द्वारा तारीख को मृत्यु दंड भोगने का दंडादेश दिया गया है, को (ङ) द्वारा जारी किये गये वारंट के अधीन (घ) कारावास में रखा गया है।

और क्योंकि उक्त दंडादेश की (ङ) द्वारा पुष्टि कर दी गई है अतः दंडादेश के पुष्टिकरण को प्रमाणित करते हुए पुष्टिकरण प्राधिकारी के आदेश की एक प्रति इससे साथ उपाबद्ध की जा रही है।

इसलिये आपको प्राधिकृत किया जाता है और अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त को (छ) में जब तक वह मरन जाये तब तक गरदन से लटकवाकर

(छ)-----में उसे गोली से मारकर उक्त दंडादेश का निष्पादन करें। और वह वारंट (ज) को पूर्णतः द्वारा यह प्रमाणित करने हुए लौटा दें कि दंडादेश का निष्पादन कर दिया गया है।

तारीख-----

हस्ताक्षर(अ)

भाग--II

वारंट वापस करना

(संख्या)----- (रैंक)-----
(नाम)-----पर पारित उपर्युक्त दंडादेश (छ)-----
में 19-----के
-----दिन-----को-----ब्रजे कार्यान्वित
कर दिया गया।

हस्ताक्षर

भाग--III

चिकित्सा अधिकारी का प्रमाणपत्र

मैं,-----यह प्रमाणित करना हूँ कि मैंने
(संख्या)----- (संख्या, रैंक, नाम)-----
(नाम)-----जिस पर मृत्यु दंडादेश कार्यान्वित
किया गया था, के शरीर की जांच आज के दिन (छ)
-----पर कर ली गई है और ऐसी जांच करने
पर पाया कि उक्त व्यक्ति मृत था।

आज तारीख-----को (स्थान पर हस्ताक्षरित किया)

(हस्ताक्षर)

(रैंक और यूनिट)

भारत के सशस्त्र सेना बल का कमीशन प्राप्त चिकित्सा
अधिकारी

(क) मृत्युदंडादेश को कार्यान्वित करने के लिये
उत्तरदायी प्रोबोस्ट माशेल या अन्य अधिकारियों
के रैंक, नाम और पदाभिधान लिखें।

(ख) "जनरल" या "समरी जनरल" अंतःस्थापित करें।

(ग) विचारण के स्थान का नाम लिखें।

(घ) कारागार का नाम लिखें।

(ङ) उस अधिकारी का नाम और पदाभिधान लिखें
जिसने मूल वारंट पर हस्ताक्षर किये हैं।

(च) पुष्टि करने वाले प्राधिकारी का नाम और
वर्णन।

(छ) फासी का समय तारीख और स्थान।

(ज) सेना, सेना कोर या डिवाजन का समादेश करने
वाला आफिसर या फील्ड में बलों का समादेश
करने वाला आफिसर जिसने वारंट जारी किया

(अ) उस आफिसर के हस्ताक्षर जिनके द्वारा वारंट
जारी किया गया है।

(आ) दंडादेश का निष्पादन करने वाले आफिसर के
हस्ताक्षर।

प्रकरण 1--ख

सिविल कारागार में मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का
वारंट

(सेना नियम 170 क और नियम 170 ब)

भाग--I

प्रेषितो

(क) -----कारागार अधिकृत

(यूनिट) का (संख्यांक, रैंक, नाम) को-----जिसे
(ग)-----में हुए सेना न्यायालय (ख)-----द्वारा
तारीख-----को मृत्यु दंड भोगने का दंडादेश दिया
गया है, (घ)-----द्वारा जारी किये गये वारंट द्वारा
आपकी अभिरक्षा में सुदृढ़ किया गया है।

और क्योंकि उक्त दंडादेश की (ङ) द्वारा पुष्टि कर दी
गई है अतः दंडादेश के पुष्टिकरण को प्रमाणित करने
हूए पुष्टिकरण प्राधिकारी के आदेश को एक प्रति इसके
साथ उपाबद्ध की जा रही है।

इसलिये आपको प्राधिकृत किया जाता है और आगे
अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त-----को-----
(च) में जब तक यह मर न जाये तब तक गद्द
लटकवा कर उक्त दंडादेश का निष्पादन करें और यह
वारंट (छ) की पूर्णतः द्वारा यह प्रमाणित करने
हूए लौटा दें कि दंडादेश का निष्पादन कर दिया गया है।

तारीख-----

हस्ताक्षर(अ)

भाग--II

वारंट वापस करना

(संख्या)----- (रैंक)----- (नाम) -----
पर पारित उपर्युक्त दंडादेश (च) -----में
19-----के-----दिन-----को
-----ब्रजे कार्यान्वित कर दिया गया।

हस्ताक्षर

कारागार अधिकृत

(क) सिविल कारागार का नाम लिखें।

(ख) "जनरल" या "समरी जनरल" अंतःस्थापित।

(ग) विचारण के स्थान का नाम लिखें।

(घ) उस अधिकारी का पदाभिधान लिखें जिसने
मूल वारंट पर हस्ताक्षर किये हैं।

- (ड) पुष्टिकरण करने वाले प्राधिकारी का नाम और वर्णन।
- (च) फाँसी का समय, तारीख और स्थान।
- (छ) सेना, सेना कोर या विजीयर का पदनाम करने वाला आफिसर जिसने वारंट जारी किया है।
- (ज) उस आधिकारिक के हस्ताक्षर जिसके द्वारा वारंट जारी किया गया है।

टिप्पण :—सा.का.नि. 484 तारीख 27 नवम्बर, 1954 द्वारा मूल नियम अधिसूचित हुए और पश्चात्तवर्ती निम्नलिखित सा.का.नि. द्वारा संशोधन किया गया :

- (1) अ. 7, तारीख 17-6-1960
- (2) 205, तारीख 12-7-1961
- (3) 1, तारीख 22-12-1961
- (4) 34, तारीख 5-6-1963
- (5) 126, तारीख 12-3-1964
- (6) 215, तारीख 17-6-1965
- (7) 5, तारीख 23-12-1968
- (8) 188, तारीख 4-6-1979
- (9) 246, तारीख 12-10-1982
- (10) 44, तारीख 24-1-1985
- (11) 55, तारीख 22-2-1985
- (12) 68, तारीख 1-4-1985
- (13) 278, तारीख 29-11-1985
- (14) 169, तारीख 15-5-1987
- (15) 302, तारीख 18-9-1987
- (16) 216, तारीख 30-8-1988
- (17) 332, तारीख 26-9-1989
- (18) 44, तारीख 1-2-1991
- (19) 61, तारीख 7-2-1991
- (20) 235, तारीख 1-10-1991

[फा.सं. 4(2)/93-डी(एजी)
जी.एस.एन मूर्ती, उप सचिव

MINISTRY OF DEFENCE NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 1993

S.R.O. 17(E).—In exercise of the powers conferred by Section 191 of the Army Act, 1950 (46 of 1950), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Army Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Army (Amendment) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Army Rules, 1954, (hereinafter referred to as the said rules), for sub-rules (4) and (5) of rule 14, the following sub-rules shall be substituted, namely :—

“(4) When submitting a case to the Central Government under the provisions of sub-rule (2) or sub-rule (3), the Chief of the Army Staff shall make his recommendation whether the officer's service should be terminated and if so, whether the officer should be :

- (a) dismissed from the service ; or
- (b) removed from the service ; or
- (c) compulsorily retired from the service.

(5) The Central Government after considering the reports and the officer's defence, if any, or the judgment of the criminal court, as the case may be, and the recommendation of the Chief of the Army Staff, may—

- (a) dismiss or remove the officer with or without pension or gratuity ; or
- (b) compulsorily retire him from the service with pension and gratuity,

if any, admissible to him”.

3. For rule 16A of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

“16A. Retirement of Officers.—(1) Officers shall be retired from service under the orders of the Central Government, or the authorities specified in sub-rule (2), with effect from the afternoon of the last date of the month in which they—

- (a) attain the age limits specified in sub-rule (5) ; or
- (b) complete the tenures of appointment specified in sub-rule 5(f) (ii) and (g) (ii) and sub-rule (6), whichever is earlier.

(2) The authorities referred to in sub-rule (1) shall be :

- (a) the Director General Armed Forces Medical Services in respect of Officers of the Army Medical Corps, Army Dental Corps and Military Nursing Service ;
- (b) the Additional Director General, Remount and Veterinary Corps in respect of Officers of that Corps below the rank of Colonel ;
- (c) the Deputy Director General of Military Farms in respect of Officers of the Military Farms below the rank of Colonel ;
- (d) the Military Secretary, Army Headquarters in respect of all other Officers.

(3) The orders shall specify the date from which retirement shall be effective and subject to the provisions of sub-rule (4), the Officer shall be relieved of his duties on that date.

(4) An Officer who has attained the age of retirement or has become due for such retirement on completion of his tenure, may be retained in the service for a further period by the Central Government, if the exigencies of the service so requires.

(5) The following shall be the age of retirement for Officers :—

(a) of Armoured Corps, Infantry, Artillery, Engineers and Signals :

Upto and including the rank of Major — 50 years

Lieutenant Colonel (Time Scale) — 51 years

Lieutenant Colonel (Selection) — 52 years

Colonel — 52 years

Brigadier — 54 years

Major General — 56 years

Lieutenant General — 58 years

General — 60 years

(b) of Army Service Corps (excluding Food Inspection Organisation), Army Ordnance Corps, Electrical and Mechanical Engineers, Pioneer Corps and Intelligence Corps :

Upto and including the rank of Colonel — 52 years

Brigadier — 54 years

Major General — 56 years

Lieutenant General — 58 years

(c) of Food Inspection Organisation :

Upto and including the rank of Lieutenant Colonel (Time Scale) — 52 years

Lieutenant Colonel (Selection) — 55 years

(d) of Judges Advocate General's Department, Army Education Corps, Military Farms, Special List Officers (Quartermaster), Technical Record Officers and Army Physical Training Corps (Master-at-Arms) and Remount and Veterinary Corps) :

Upto and including the rank of Colonel — 55 years

Brigadier — 56 years

Major General — 57 years

Lieutenant General — 58 years

(e) of Army Medical Corps, Army Dental Corps and Military Nursing Service :

Upto and including the rank of Lieutenant Colonel — 55 years

Colonel — 57 years

Brigadier — 58 years

Major General — 59 years

Lieutenant General — 60 years

All officers of Army Medical Corps (Non Technical) 55 years

(f) (i) permanently seconded to Defence Research and Development Organisation :

Upto and including the rank of Major General or equivalent — 57 years

Lieutenant General — 58 years

Provided that officers upto the rank of Major General or equivalent shall be given two reviews ; one at the age of 52 years and the other at the age of 55 years, carried out well in advance by the Defence Research and Development Organisation Selection Board per its own laid criteria, to determine the suitability for continuation beyond that age unless the officer volunteers for retirement. The officers found unsuitable for continuation in either of review shall retire on attaining the age of 52 years or 55 years, as the case may be.

(ii) the tenure in the substantive rank of Lieutenant General shall be four years.

(g) (i) permanently seconded to Directorate General Quality Assurance :

Upto and including the rank of Major General or equivalent — 57 years

Lieutenant General — 58 years

Provided that officers upto the rank of Major General or equivalent shall be given two reviews ; one at the age of 52 years and the other at the age of 55 years, carried out well in advance by the Inspection Selection Board per its own laid criteria, to determine the suitability for continuation beyond that age. The officers found unsuitable for continuation in either of reviews shall retire on attaining the age of 52 years or 55 years, as the case may be.

(ii) the tenure in the rank of Lieutenant shall be four years.

(h) of Engineers permanently seconded to Survey of India as under the civil rules applicable to them from time to time.

(6) The following shall be the tenures of appointment for the purpose of retirement :

(a) The tenure in the rank of a General shall be a maximum of 3 years.

(b) Army Medical Corps Officers holding the rank of Lieutenant General shall serve in that rank for one tenure of 4 years :

Provided an officer holding the appointment of Director General Medical Services (Army) or Director General Medical Services

(Navy) or Director General Medical Services (Air) or Commandant Armed Forces Medical College or Commandant Army Medical Corps School and Centre, Lucknow or Additional Director General Armed Forces Medical Services in the rank of Lieutenant General shall, in the event of his being appointed as Director General Armed Forces Medical Services, shall serve for a combined tenure of 5 years.

- (c) The tenure of Army Dental Corps Officers of the rank of Major General shall be a maximum of 4 years.

Explanation I—For the purpose of this rule,—

- (a) "Lieutenant Colonel" means a Lieutenant Colonel by selection and includes a Lieutenant Colonel by time scale in the Army Medical Corps, Army Dental Corps and Veterinary Cadre of Remount and Veterinary Corps;

- (b) "rank" means a substantive rank.

Explanation II—For the purpose of this rule,—

- (a) Age of retirement as specified in sub-rule (5) shall apply to permanent commissioned officers in their respective substantive ranks.
- (b) Stipulated age of retirement in the rank of Lieutenant General/Major General in Army Education Corps, Intelligence Corps, Remount and Veterinary Corps, Judge Advocate General's Department, Pioneer Corps, Military Farms and Special List Officers Cadre will be applicable only when these ranks are sanctioned in the Corps, Department or Cadre, as the case may be.
- (c) Officers of the Intelligence Corps, Judge Advocate General's Department, Army Education Corps, Remount and Veterinary Corps and Military Farms who had opted to be governed by the age of retirement prevalent prior to the issue of Government of India, Ministry of Defence, letter Nos A/49453/AG/PS2(a)/3770-S/D (AG) dated 26 Jul 1984 and A/49453/AG/PS2(a)/Minor Corps-S/D (AG) dated 26 Jul 1985, as applicable, shall continue to be so governed."

4. In rule 16-B of the said rules, the word "compulsory" shall be omitted.

5. For rule 22 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"22. Hearing of charge.—(1) Every charge against a person subject to the Act shall be heard by the Commanding Officer in the presence of the accused. The accused shall have full liberty to cross-examine any witness against him, and to call such witness and make such statement as may be necessary for his defence :

Provided that where the charge against the accused arises as a result of investigation by a court of inquiry, wherein the provisions of rule 180 have been complied with in respect of that accused, the commanding officer may dispense with the procedure in sub-rule (1).

- (2) The commanding officer shall dismiss a charge brought before him, if, in his opinion, the evidence does not show that an offence under the Act has been committed, and may do so if he is satisfied that the charge ought not to be proceeded with :

Provided that the commanding officer shall not dismiss a charge which he is debarred to try under sub-section (2) of sec-120 without reference to superior authority as specified therein.

- (3) After compliance of sub-rule (1), if the commanding officer is of opinion that the charge ought to be proceeded with, he shall within a reasonable time—

- (a) dispose of the case under section 80 in accordance with the manner and form in Appendix III; or
- (b) refer the case to the proper superior military authority; or
- (c) adjourn the case for the purpose of having the evidence reduced to writing; or
- (d) if the accused is below the rank of warrant officer, order his trial by summary court-martial :

Provided that the commanding officer shall not order trial by a summary court-martial without a reference to the officer empowered to convene a district court-martial or on active service a summary general court-martial for the trial of the aggrieved offender unless—

- (a) the offence is one which he can try by a summary court-martial without any reference to that officer; or
- (b) he considers that there is grave reason for immediate action and such reference cannot be made without detriment to discipline.

- (4) Where the evidence taken in accordance with sub-rule (3) of this rule discloses an offence other than the offence which was the subject of the investigation, the commanding officer may frame suitable charge(s) on the basis of the evidence so taken as well as the investigation of the original charge."

6. Rule 25 of the said rules, shall be omitted.

7. In rule 26 of the said rules,—

- (i) in sub-rule (1), the words "or (in the case of an officer where there is no summary of evidence) an abstract of the evidence to be adduced", shall be omitted.

- (ii) in sub-rule (3), the words "or abstract", shall be omitted.

8. In sub-rule (7) of rule 33 of the said rules, the following words shall be omitted, namely :—

"or in the case of an officer where there is no summary of evidence, an abstract of evidence".

9. In rule 36 of the said rules, the figure "25", shall be omitted.

10. In sub-rule (4) of rule 37 of the said rules, the words "or abstract" occurring at both the places shall be omitted.

11. After sub-rule (2) of rule 52 of the said rules, the following sub-rule (2A) shall be inserted, namely :—

"(2A) Where an accused pleads Guilty, such plea and the factum of compliance of sub-rule (2) of this rule, shall be recorded by the court in the following manner :—

Before recording the plea of Guilty of the accused, the court explained to the accused the meaning of the charge(s) to which he had pleaded Guilty and ascertained that the accused had understood the nature of the charge(s) to which he had pleaded Guilty. The court also informed the accused the General effect of the plea and the difference in procedure, which will be followed consequent to the said plea. The court having satisfied itself that the accused understands the charge(s) and the effect of his plea of Guilty, accepts and records the same. The provisions of rule 52 (2) are thus complied with."

12. For clause (c) of sub-rule (1) of rule 53 of the said rules, the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) the period of limitation for trial as laid down in section 122 has expired".

13. For rule 54 of the said rules, the words "or abstract" wherever they occur shall be omitted.

14. For rule 57 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"57. Plea of no case.—(1) At the close of the case for the prosecution, the accused may offer a plea that the evidence given on behalf of the prosecution, in respect of any one or more charges, has not established a prima-facie case against him and that he should not, therefore, be called upon to make his defence to that charge or charges.

(2) Where the accused takes such a plea, the prosecutor may address the court in answer thereto and the accused may reply.

(3) The court shall consider the plea in closed court and shall not allow the plea unless

satisfied that—

(a) the prosecution has not established a prima-facie case on the charge or charges as laid; and

(b) it is not open to it on the evidence adduced to make a special finding either under section 139 or sub-rule (4) of rule 62.

(4) If the court allows the plea, it shall record a finding of "Not Guilty" on the charge or charges, to which the plea relates, and shall announce the finding forthwith in open court as subject to confirmation.

(5) If the court over rules the plea, it shall proceed with the trial.

(6) If the court has any doubt as to the validity of the plea, it may refer the matter to the convening authority, and adjourn for that purpose.

(7) The court may, of its own motion, after the close of the case for the prosecution, and after hearing the prosecutor find the accused "Not Guilty" of the charge, and announce the finding forthwith in open court as subject to confirmation.

(8) The court shall record brief reasons while arriving at the finding on the plea, in accordance with sub-rule (1) of rule 62."

15. For rule 58 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"58. Examination of the accused and defence witnesses.—(1) (a) In every trial, for the purpose of enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in evidence against him, the court or the Judge Advocate—

(i) may at any stage, without previously warning the accused, put such questions to him as considers necessary;

(ii) shall, after the close of the case for the prosecution and before he is called on for his defence, question him generally on the case.

(b) No oath shall be administered to the accused when he is examined under clause (a).

(c) The accused shall not render himself liable to punishment by refusing to answer questions referred in clause (a) above, or by giving answers to them which he knows not to be true.

(2) After the close of the case for the prosecution, the presiding officer or the judge advocate, if any, shall explain to the accused that he may make an unsworn statement, orally or in writing, giving his account of the subject of the charge(s) against him or if he wishes, he may give evidence as a witness, on oath or affirmation, in disproof of the charge(s) against him or any person charged together with him at the same trial :

Provided that—

- (a) he shall not be called as a witness except on his own request in writing;
- (b) his failure to give evidence shall not be made the subject of any comment by any of the parties or the court or give rise to any presumption against himself or any person charged together with him at the same trial;
- (c) if he gives evidence on oath or affirmation, he shall be examined as first witness for defence and shall be liable to be cross-examined by the prosecutor and to be questioned by the court.

- (3) The accused may then call his witnesses including, if he so desires, any witnesses as to character. If the accused intends to call witnesses as to the facts of the case other than himself, he may make an opening address before the evidence for defence is given".

16. For rule 59 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"59. Closing Addresses.—After the examination of the witnesses, the prosecutor may make a closing address and the accused or his counsel or the defending officer, as the case may be, shall be entitled to reply :

Provided that where any point of law is raised by the accused, the prosecutor may, with the permission of the court, make his submission with regard to that point".

17. Rule 59-A of the said rules, shall be omitted.

18. For sub-rule (1) of rule 62 of the said rules, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) The finding on every charge upon which the accused is arraigned shall be recorded and, except as provided in these rules, shall be recorded as finding of 'Guilty' or of 'Not Guilty'. After recording the finding on each charge, the court shall give brief reasons in support thereof. The judge advocate or, if there is none, the presiding officer shall record or cause to be recorded such brief reasons in the proceedings. The above record shall be signed and dated by the presiding officer and the judge advocate, if any".

19. For rule 68 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"68. Revision.—(1) Where the finding is sent back for revision under section 160, the court shall re-assemble in open court, the revision order shall be read, and if the court is directed to take fresh evidence, such evidence shall also be taken in open court.

- (2) Except where the court is directed to take fresh evidence, no fresh evidence shall be adduced.

- (3) The court may, on a request from the prosecutor, in the interest of justice, allow a witness to be called or re-called for the purpose of rebutting any material statement made by a witness for the defence during revision.

- (4) After the revision order has been read in open court, whether the revision is of finding or sentence and the evidence, if any, in accordance with sub-rule (1), (2) and (3) has been taken, the prosecutor and the accused shall be given a further opportunity to address the court in the order as laid down in rule 59. If necessary, the judge-advocate, if any, may sum up the (additional) evidence and advise the court upon the law relating to the case. The court shall then deliberate on its finding or the sentence, as the case may be, in closed court.

- (5) Where the finding is sent back for revision and the court does not adhere to its former finding, it shall revoke the finding and sentence, and record the new finding, in the manner laid down in rule 62, and if such new finding involves a sentence, pass sentence afresh, after complying with rule 64.

- (6) Where the sentence alone is sent back for revision, the court shall not revise the finding.

- (7) After the revision, the presiding officer shall date and sign the decision of the court, and the proceedings, upon being signed by the judge-advocate, if any, shall at once be transmitted for confirmation".

20. In sub-rule (1) of rule 92 of the said rules, for the words, "in the English language" the following shall be substituted, namely :—

"in the Hindi or English language".

21. For rule 96 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"96. Counsel allowed in general and district courts-martial.—In every general and district court-martial, counsel shall be allowed to appear on behalf of the prosecutor as well as the accused :

Provided the convening officer may declare that it is not expedient to allow the appearance of counsel thereat and such declaration may be made as regards all general and district courts-martial held in any particular place, or as regards any particular general or district court-martial, and may be made subject to such reservation as to cases on active service, or otherwise, as deemed expedient.

22. In sub-rule (1) of rule 106 of the said rules, for the words, "in the English language", the following said plea. The court having satisfied

"in the Hindi or English language".

23. In rule 115 of the said rules, after sub-rule (2), the following sub-rule (2A) shall be inserted, namely :—

“(2A) Where an accused pleads Guilty, such plea and the factum of compliance of sub-rule (2) of this rule, shall be recorded by the court in the following manner :—

Before recording the plea of Guilty of the accused, the court explained to the accused the meaning of the charge(s) to which he had pleaded Guilty and ascertained that the accused had understood the nature of the charge(s) to which he had pleaded Guilty. The court also informed the accused the general effect of the plea and the difference in procedure, which will be followed consequent to the said plea. The court having satisfied itself that the accused understands the charge(s) and the effect of his plea of Guilty, accepts and records the same. The provisions of rule 115(2) are thus complied with”.

24. In rule 118 of the said rules, the following words shall be omitted, namely :—

“but the court may draw such inference from such refusal of answers as it thinks just”.

25. In rules 134, 135 and 136 of the said rules, the words, “or abstract” shall be omitted.

26. For rule 145 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

“145. Finding of Insanity.—(1) Where the court finds either that the accused by reason of unsoundness of mind, is incapable of marking his defence; or that he committed the act alleged but was by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing the nature of the act or that it was wrong or contrary to law, the court shall give brief reasons in support thereof. The judge advocate, if any, or the presiding officer or in the case of summary court-martial, the officer holding the trial shall record or cause to be recorded such brief reasons in the proceedings.

(2) The presiding officer or in the case of summary court-martial, the officer holding the trial, shall date and sign the above record, and the proceedings upon being signed by the judge-advocate, if any, shall at once be transmitted to the confirming officer or to the authority empowered to deal with its finding under section 162, as the case may be.”

27. In sub-rule (3) of rule 150 of the said rules, for the words and figures, “section 476 of the Code of Criminal Procedure, 1893 (Act V of 1893)”, the words and figures “section 340 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act. 2 of 1974)”, shall be substituted.

2787 GI/93—3

28. In rule 159 of the said rules,—

(a) In sub-rule (1) the following words shall be omitted, namely:—

“Whether a legal adviser or any other person”;

(b) In sub-rule (2) the following words shall be omitted namely :—

“but the court may draw such inference from such refusal or answers as it thinks just”.

29. In sub-rule (3) of rule 160 of the said rules, the words “or abstract” shall be omitted.

30. In rule 164 of the said rules,—

(i) the figure and words “25 (procedure on charge against officer)”, shall be omitted;

(ii) after the figure and words “95 (defending officer and friend of accused)”, the following figures and words shall be inserted, namely :—

“96 (counsel allowed in certain general and district court-martial), 97 (requirement for appearance of counsel), 98 (counsel for prosecution), 99 (counsel for accused), 100 (general rules as to counsel), 101 (qualification of counsel)”.

31. In sub-rule (2) of rule 168 of the said rules, the words, “or with field punishment” and “or until the completion of the field punishment, unless such field punishment is remitted by a competent authority”, shall be omitted.

32. For rule 170 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

“170. Opportunity for petition against sentence of death.—(1) While confirming the sentence of death, the confirming authority shall specify the period within which the person sentenced may, after the sentence has been promulgated to him, submit a petition against the finding or sentence against him of the court-martial

(2) The person against whom a sentence of death has been confirmed shall at the time of promulgation, be informed of his rights under sub-section (2) of section 164 and of the period specified by the confirming authority within which he may, if he so wishes to do, submit a petition against the finding or sentence of the court-martial.

(3) Every petition against a finding or sentence submitted by a person against whom a sentence of death has been confirmed, and every order in respect of such petition shall be transmitted, whereas confirming authority is the Chief of the Army Staff or the Central Government, through the Adjutant General at the Army Headquarters and in any other case, through the confirming officer.

- (4) A sentence of death shall not be carried into effect until the expiry of the period specified by the confirming authority under sub-rule (1) or if, within the period so specified, the person under sentence submits a petition against the finding or sentence of the court-martial, until the authority legally competent to dispose of such petition finally, after considering the petition, orders that the sentence of death may be carried into effect."

33. After rule 170 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely :—

"170A. Death Warrant.—(1) The officer commanding the army, army corps or division or an officer commanding forces in the field shall nominate a provost marshal or other officer not below the rank of Lieutenant Colonel who shall be responsible for the due execution of the sentence of death passed under the Act, and shall issue to such officer the death warrant in the relevant form contained in Appendix V.

- (2) The officer specified in sub-rule (1) shall not issue the death warrant until he is satisfied that having regard to the provisions of rule 170, the sentence of death may be carried into effect.
- (3) No sentence of death passed under the Act shall be carried into effect until the death warrant has been received by the provost marshal or other officer nominated under sub-rule (1).
- (4) If the authority specified in sub-rule (1) is of the opinion that the sentence of death be carried out in a civil prison, he shall forward a warrant in one of the forms in Appendix V together with an order of the confirming authority certifying the confirmation of the sentence, to the civil prison for execution of the sentence.

170B. Execution of sentence of death.—(1) On receipt of the death warrant, the provost marshal or other officer, nominated under sub-rule (1) of rule 170A shall :—

- (a) inform the person sentenced as soon as possible of the date on which the sentence will be carried out;
- (b) if the person sentenced has been committed to a civil prison under rule 169 obtain the custody of his person by issuing a warrant in one of the forms in Appendix V; and
- (c) proceed to carry out the sentence as required by the death warrant and in accordance with any general or special instructions which may from time to time be given by or under the authority of the Chief of the Army Staff.

- (2) During the execution of a sentence of death passed under the Act, no person except those

specified below, shall be present without the authority of the officer who issued the death warrant. The following persons shall attend the execution of the sentence of death :—

- (a) the provost marshal or other officer who is responsible for the due execution of the sentence in accordance with these rules;
- (b) a commissioned medical officer of the armed forces of the Union;
- (c) an officer nominated by the officer who issued the death warrant, who is able to identify the person under sentence as the person described in the death warrant and as the person who was tried and sentenced by the court martial mentioned therein;
- (d) such non-commissioned officers as may be detailed by the provost marshal or the other officer aforesaid for escort and security purposes or to assist in the execution;
- (e) if the execution is carried into effect in an army unit, the officer for the time being in command of such unit.
- (3) After the sentence of death has been carried into effect, the provost marshal or other officer nominated under sub-rule (1) of rule 170A or the Superintendent of the civil prison, as the case may be, shall complete or cause to be completed parts II and III of the death warrant, and shall without unnecessary delay return the completed death warrant to the officer who had issued the same".

34. The heading "SECTION 7—Field Punishment" before rule 172 and rules 172 to 176 (both inclusive) of the said rules shall be omitted.

35. In rule 179 of the said rules, after sub rule (5), the following sub rule shall be inserted, namely :—

"(5A) Any witness may be summoned to attend by order under the hand of the officer assembling the Court. The summons shall be in the Form provided in Appendix III."

36. For rule 182 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"182. Proceedings of court of inquiry not admissible in evidence.—The proceedings of a court of inquiry, or any confession, statement, or answer to a question made or given at a court of inquiry, shall not be admissible in nor shall any evidence respecting the proceedings of the court be given against any such person except upon the trial of such person for wilfully giving false evidence before the court;

Provided that nothing in this rule shall prevent the proceedings from being used by the prosecution or the defence for the purpose of cross-examining any witness".

37. For sub-rule (1) of Rule 186 of the said rules, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(1) The officer commanding the army, army corps, division or independent brigade shall then record his opinion on the circumstances of the loss or theft, and may impose for each weapon or part of a weapon lost or stolen, collective fines to the extent of the current official prices of such weapons or part of weapons on the junior commissioned officers, warrant officers, non-commissioned officers, and men of such unit or upon so many of them as he considers should be held responsible for the occurrence”.

38. For rule 193 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

“193. Prescribed Officer under Section 90(i) and 91(i).—The prescribed officer for the purposes of clause (i) of section 90 and clause (i) of section 91 shall be the Chief of the Army Staff or the officer commanding the Army”.

39. In APPENDIX III to the said rules,—

(a) in PART I, in IAFD-905 (STATEMENT AS TO CHARACTER AND PARTICULARS OF SERVICE OF ACCUSED), for para 9, the following para shall be substituted, namely :—

“9. The accused has been under arrest/~~confinement during investigation, inquiry or trial relating to the same case for~~— days in civil custody and— days in military custody, making a total of— days”.

(b) in PART III “FORMS OF SUMMONS TO WITNESSES”, after Form ‘(b) in the case of a Court Martial’ and the entries relating thereto, the following Form shall be added, namely :—

“(c) In the case of a Court of Inquiry IAFD-919C To—
Whereas a Court of Inquiry has been ordered to assemble at—
on the—day—19—
for investigating into—. I do hereby summon and require you A—
—B—to attend as a witness at the sitting of the said Court at—(Place) on the—(day), at—hrs, and to bring with you the documents hereinafter mentioned, namely—, and so to attend from day to day until you shall be duly discharged, whereof you shall fail at your peril.

Given under my hand at—on the—day of—19—.

Signature

Officer Assembling the Court of Inquiry”

40. In APPENDIX IV to the said rules, in PART II “WARRANTS UNDER SECTIONS 168, 169(2) AND 173 OF THE ARMY ACT,—

(a) in FORM B,—

(i) the following para, before the sentence “Given under my hand at—this the—day of—19”, shall be inserted, namely :—

“The period spent by (Name)—in civil custody/military custody during the investigation, inquiry or trial of the same case is(.)—and the said period (ff)—shall be set off against the aforesaid sentence of imprisonment.”;

(ii) after serial number (f), the following explanation shall be inserted, namely :—

“(ff) Enter the exact period (years, months and days) spent in military/civil custody during investigation, inquiry or trial in the same case.”;

(b) in FORM C,—

(i) The following para, before the sentence “Given under my hand at—this—day of—19”, shall be inserted, namely :—

“the period spent by (Name)—in civil custody/military custody during the investigation, inquiry or trial of the same case is (dd)—and the said period (dd)—shall be set off against the aforesaid sentence of imprisonment.”;

(ii) after serial number (d) the following explanation shall be inserted, namely :—

“(dd) Enter the exact period (years, months and days) spent in military/civil custody during investigation, inquiry or trial in the same case.”

41. In APPENDIX V to the said rules,—

(a) in the heading, “WARRANTS UNDER ARMY RULES 169, 170 AND 171”, for the existing figure “170”, the figure “170A” shall be substituted;

(b) in “FORM I” for the existing figure “170”, the figure “170A” shall be substituted;

- (c) after FORM I and the entries relating thereto, the following new Forms shall be added, namely :—

"FORM 1-A

WARRANT OF EXECUTION ON SENTENCE OF DEATH BY MILITARY AUTHORITIES

(Army Rules 170A and 170B)

PART-I

To,

(a)

Whereas (Number, Rank, name)..... of the.....(Unit) having been sentenced to suffer death on the.....day of.....19.....by a (b) court martial held at.....(c), is held in the (d) prison under a Warrant issued by (e);

AND Whereas, the said sentence, having been confirmed by (f) a copy of the order of the confirming authority certifying the confirmation of the sentence being annexed hereto;

This is to authorise and require you to carry the said sentence into execution by causing the said.....to be hanged by the neck until he be dead at (g).....to be shot to death at (g).....and to return this warrant to (h) with an endorsement certifying that the sentence has been executed.

Dated, this.....day of.....19.....

Signature (i)

PART II

Return of Warrant

The above sentence passed on (number).....(rank).....(name)..... was carried into effect at (g).....hours on the.....day of.....19.....

Signature (j).....

PART III

Certificate of Medical Officer

I,.....hereby certify that I have (Number, rank, name)..... examined the body of (number).....(rank).....(name)..... upon whom the sentence of death was carried into effect, this day, at (g).....and that on such examination I found that the said person was dead.

Signed at.....this the.....(place) day of.....19.....

(Signature).....

(Rank and Unit).....
Commissioned medical officer of the Armed Forces of India

- (a) Enter the rank, name and designation of provost marshal or other officer responsible for carrying the sentence of death into effect.
(b) Insert "General" or "Summary General".
(c) Enter the place of trial.
(d) Enter the name of the prison.
(e) Enter name and designation of officer who signed the original warrant.
(f) Name and description of confirming authority.
(g) Time, date and place of execution.
(h) The Officer Commanding the Army, Army Corps or Division or an Officer Commanding Forces, in the field, who has issued the warrant.
(i) Signature of the officer by whom the warrant is issued.
(j) Signature of the officer executing the sentence.

FORM I-B

WARRANT OF EXECUTION OF SENTENCE OF DEATH IN CIVIL PRISON

(Army Rules 170A and 170B)

PART I

To,

The Superintendent of the (a)..... Prison Whereas (Number, Rank, Name)..... of the.....(Unit) having been sentenced to suffer death on the.....day of.....19.....by a (b) court martial held at.....(c), has been by a warrant issued by (d) committed to your custody;

AND Whereas, the said sentence having been confirmed by (e), a copy of the order of the confirming authority certifying the confirmation of the sentence being annexed hereto; This is to authorise and require you to carry the said sentence into execution by causing the said.....TO BE HANGED BY THE NECK UNTIL HE BE DEAD AT (f).....and to return his warrant to (g) with an endorsement certifying that the sentence has been executed

Dated, this.....day of.....19.....

Signature (h).....

PART II

Return of Warrant

The above sentence passed on (number).....(rank).....(name)..... was

carried into effect at (f).....hours on
the.....day of.....

Signature _____

Superintendent of Prison

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) Insert "General" or "Summary General".
- (c) Enter the place of trial.
- (d) Enter name and designation of officer who signed the original Warrant.
- (e) Name and description of confirming authority.
- (f) Time, date and place of execution.
- (g) The officer commanding the Army, Army corps or division or an officer commanding forces in the field, who has issued the warrant.
- (h) Signature of the officer by whom the order is issued."

Note : The principal rules were notified vide number S.R.O. 484, dated the 27th November 1954 and subsequently amended vide numbers S.R.O. :

- (1) E. 7, dated 17-6-1960.
- (2) 205, dated 12-7-1961.

- (3) 1, dated 22-12-1961.
- (4) 34, dated 5-6-1963.
- (5) 126, dated 12-3-1964.
- (6) 215, dated 17-6-1965.
- (7) 5, dated 23-12-1968.
- (8) 188, dated 04-6-1979.
- (9) 246, dated 12-10-1982.
- (10) 44, dated 24-1-1985.
- (11) 55, dated 22-2-1985.
- (12) 68, dated 01-4-1985.
- (13) 278, dated 29-11-1985.
- (14) 169, dated 15-5-1987.
- (15) 302, dated 18-9-1987.
- (16) 216, dated 30-8-1988.
- (17) 332, dated 26-9-1989.
- (18) 44, dated 01-2-1991.
- (19) 61, dated 07-2-1991.
- (20) 235, dated 01-10-1991.

[File No. 4(2)|93-D(AG)]

G. S. N. MURTHY, Dy. Secy. (AG)

